

जे. वी. गोकल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

सहायक कलेक्टर बिक्री-कर (निरीक्षण) और अन्य

(बी. पी. सिन्हा, सी. जे., पी. बी. गजेन्द्र गढ़कर, के. सुब्बा राव, के. सी. दास गुप्ता
और जे. सी. शाह, जे. जे.)

बिक्री कर-आयात के दौरान बिक्री-गहरे समुद्रों में माल-भुगतान के बदले शिपिंग दस्तावेजों का हस्तांतरण-क्या माल की डिलीवरी के बराबर है-क्या लेनदेन को भारत के संविधान, अनुच्छेद 286 (आर) (बी) से कर से छूट दी गई है।

विदेशी मूल की चीनी की कुछ मात्रा की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के साथ अनुबंध करने वाले याचिकाकर्ता ने विदेशों में विक्रेताओं को आदेश दिए और स्टीमरों को संलग्न करके बॉम्बे में माल के परिवहन की व्यवस्था की। जब माल समुद्र में था और जहाजों के बॉम्बे बंदरगाह पर पहुंचने से पहले, याचिकाकर्ता ने सरकार को माल से संबंधित माल के बिल सहित शिपिंग दस्तावेज दिए और कीमत प्राप्त की। बंदरगाह पर माल पहुंचने के बाद, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद भारत सरकार द्वारा उनकी डिलीवरी की गई। निर्धारण वर्ष 1954-55 के लिए, बिक्री कर के सहायक कलेक्टर ने अभिनिर्धारित किया कि सरकार को बेची गई चीनी से संबंधित लेनदेन के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री कर का भुगतान किया जाना था। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ दावा किया कि बिक्री आयात के दौरान हुई थी और इसलिए वे भारत के संविधान की धारा 286 (1) (बी) के तहत बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन बिक्री कर प्राधिकरणों के लिए यह तर्क दिया गया कि बिक्री आयात के क्रम में नहीं थी और किसी भी मामले में, अनुबंधों की शर्तों के तहत पक्षों

का इरादा यह था कि भुगतान के खिलाफ लदान के बिलों के वितरण के बावजूद माल में संपत्ति को वास्तविक वितरण होने तक सरकार को नहीं देना चाहिए।

अभिनिर्धारित किया गया:-

(1) वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 (आर) (बी) के अनुसार माल के आयात का क्रम उस समय शुरू होता है जब माल विदेश के सीमा शुल्क अवरोध को पार करता है और माल के सीमा शुल्क अवरोध को पार करने के बाद आयातक देश में एक बिंदु पर समाप्त होता है;

(2) कि एक आयातक, यदि वह प्रेषण दस्तावेज प्राप्त करता है, तो माल में संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर सकता है, जब वे भुगतान के खिलाफ प्रेषण दस्तावेज भेजते हैं और ऐसी बिक्री आयात के दौरान की जाती है;

(3) जब माल तैर रहा हो तो लेडिंग बिल की डिलीवरी माल की डिलीवरी के बराबर है; सैंडर्स ब्रदर्स बनाम मैक्लीन एंड कंपनी, (1883) द्वितीय प्रश्न, बी. डी. 327, पर निर्भर था।

(4) कि विचाराधीन अनुबंधों के सही निर्माण पर माल में संपत्ति भारत सरकार को पारित कर दी गई जब शिपिंग दस्तावेज भुगतान के बदले उन्हें वितरित किए गए थे; और

(5) कि विचाराधीन बिक्री भारत में आयात के दौरान हुई थी और संविधान के अनुच्छेद 286 (आर) (बी) के तहत बिक्री कर से छूट दी गई थी।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य बनाम बॉम्बे कंपनी लिमिटेड, [1952] एस.सी.आर 1112

मौलिक क्षेत्राधिकार:-याचिका संख्या 38/1959

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका।

याचिकाकर्ता के लिए पुरुषोत्तम त्रिकुमदास और आई. एन. श्रॉफ।

उत्तरदाताओं के लिए ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, आर. गणपति अय्यर और आर. एच. डेबर।

एन. ए. पालखीवाला और आई. एन. श्रॉफ, मध्यस्थ संख्या 1 से 3 (द बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बॉम्बे और अन्य) के लिए।

सी. के. दफतरी भारत के सॉलिसिटर जनरल और टी. एम. सेन, मध्यस्थ संख्या 4 (भारत के लिए अटॉर्नी-जनरल) के लिए।

25 जनवरी 1960

न्यायालय का निर्णय सुब्बा राव, जे. द्वारा दिया गया था।

यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 9 फरवरी, 1959 के पहले प्रतिवादी के आदेश को रद्द करने के लिए एक याचिका है, जिसमें दूसरे प्रतिवादी के आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें रुपये 1,86,42,730-15-0 की राशि की कटौती की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता के बिक्री कर हस्तांतरण से इस आधार पर कि उक्त राशि बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम III) की धारा 46 के आधार पर कर के लिए उत्तरदायी नहीं थी, (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है)।

भौतिक तथ्य विवाद में नहीं हैं और उन्हें संक्षेप में कहा जा सकता है: याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिनियम, 1956 अर्थ में एक निजी कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय कस्तूरी भवन, बॉम्बे-1 में है। 24 मार्च, 1954 और 15 अप्रैल, 1954

को याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के साथ चीनी की दो खेपों को बेचने के लिए दो अनुबंध किए-एक पेरू मूल की 9500 टन चीनी और दूसरा महाद्वीपीय मूल की 25000 मीट्रिक टन चीनी। अनुबंधों की शर्तों को पूरा करने के लिए, याचिकाकर्ता ने विदेशों में विक्रेताओं को आदेश दिया। 9500 टन चीनी की आपूर्ति के लिए पहले अनुबंध दिनांकित 24 मार्च 1954 से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं।

(i) 3 अप्रैल, 1954 याचिकाकर्ता द्वारा खोला गया साख पत्र।

(ii) 3 मई, 1954 एस. एस. अल्बा सलावेरी (पेरू) से 9782.01688 लंबी टन चीनी लेकर रवाना हुए।

(iii) 26 मई, 1954 याचिकाकर्ता ने अपने बैंकरो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे को रुपये 50,35,405-11-0 के चालान के साथ वितरित किया। स्वामित्व के दस्तावेज (अर्थात् उपरोक्त वस्तुओं के लिए भारत सरकार, खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि) के पक्ष में विधिवत समर्थन किए गए लेडिंग बिल) अन्य दस्तावेजों (जैसे प्रमाण पत्र) के साथ और उक्त बैंकरो को निर्देश दिया कि वे इसे भारत सरकार को प्रस्तुत करें, और उक्त राशि 50,35,405-11-0 को उप महालेखाकार (खाद्य और पुनर्वास), नई दिल्ली से एकत्र करें।

(iv) 7 जून, 1954 भारत सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के बैंकरो को चालान और लेडिंग बिलों के वितरण के विरुद्ध किया गया भुगतान।

(v) 26 जून, 1954 बॉम्बे हार्बर पर एस. एस. अल्बा के आगमन की तिथि। दूसरे अनुबंध से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:

(iv) 22 जुलाई, 1954, 12 अगस्त, 1954, 16 अगस्त, 1954 याचिकाकर्ता ने अपने बैंकरो, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, बॉम्बे को रुपये 50,43,501-8-0, रु. 22,69,800-13-0, रु. 50,38,997-14-0 के चालान के साथ वितरित किया। क्रमशः

भारत सरकार, खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि) के पक्ष में अन्य दस्तावेजों (जैसे प्रमाण पत्र) के साथ उपरोक्त वस्तुओं के लिए विधिवत समर्थन किए गए स्वामित्व के दस्तावेज (अर्थात् लेडिंग बिल) और उक्त बैंकों को निर्देश दिया कि वे इसे भारत सरकार को प्रस्तुत करें और उक्त राशि के रूप में रु. 50,43,501-8-0, रु. 22,69,800-13-0 और रु.50,38,997-14-0 उप महालेखाकार (खाद्य और पुनर्वास) नई दिल्ली से से एकत्र करें।

(v) 26 जुलाई, 1954, 18 अगस्त, 1954, 19 अगस्त, 1954, याचिकाकर्ता के बैंकों को बॉम्बे हार्बर पर जहाज के आने की तारीख तक किया गया भुगतान, चालान और लेडिंग बिलों की डिलीवरी के खिलाफ भारत सरकार (vi) 12 अगस्त 1954 3 सितंबर, 1954 09 सितंबर, 1954, बॉम्बे हार्बर पर पोत के आगमन की तिथि।

पूर्वगामी विवरणों से पता चलता है कि जहाज के बॉम्बे बंदरगाह पर पहुंचने से कुछ हफ्ते पहले, यानी जब जहाज गहरे समुद्र में थे, भारत सरकार को उनके द्वारा खरीदी गई चीनी से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेज, जिसमें लदान के बिल शामिल थे, प्राप्त हुए और याचिकाकर्ता को कीमत का भुगतान किया। वास्तव में माल के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद, उन्हें संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद भारत सरकार द्वारा उतार दिया गया, उनकी डिलीवरी की गई और उन्हें मंजूरी दे दी गई।

1 अप्रैल, 1954 से 31 मार्च, 1955 तक के निर्धारण वर्ष के लिए, याचिकाकर्ता का मूल्यांकन बिक्री कर अधिकारी, लाइसेंस सर्कल, डिवीजन 1, बिक्री-कर बॉम्बे द्वारा बिक्री के लिए किया गया था। याचिकाकर्ता के टर्न-ओवर की गणना करते हुए, बिक्री कर अधिकारी ने याचिकाकर्ता के टर्न-ओवर से उक्त दो बिक्री की कीमत काट ली। 31 जनवरी, 1958 को, प्रथम प्रतिवादी, बिक्री कर के सहायक कलेक्टर ने अधिनियम की

धारा 31 के तहत याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया, जिसमें बिक्री कर अधिकारी द्वारा पारित उक्त मूल्यांकन आदेश की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया गया था। नियत समय में याचिकाकर्ता ने आपत्तियाँ दायर कीं और अपना अभ्यावेदन दिया। याचिकाकर्ता ने प्रथम प्रत्यर्थी के समक्ष तर्क दिया कि नोटिस अधिनियम की धारा 31 के तहत नहीं, बल्कि धारा 15 के तहत जारी किया जाना चाहिए था, क्योंकि बिक्री का खुलासा बिक्री कर अधिकारी को किया गया था और उसके द्वारा कटौती की अनुमति दी गई थी। यह भी दलील दी गई कि किसी भी स्थिति में बिक्री आयात के दौरान हुई थी और इसलिए वे बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं थे। प्रथम प्रतिवादी ने दोनों दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि उक्त दो लेन-देनों के संबंध में बिक्री कर देय था। उन्होंने याचिकाकर्ता का कुल बिक्री कर और सामान्य कर Rs.10,22,850-12-0 से कम रु. 315-3-0 याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ही भुगतान किया गया है, यानी रु. 10,22,535-9-0 और दूसरे प्रतिवादी, बिक्री कर अधिकारी को उक्त राशि के लिए मांग का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उस आदेश के अनुसार, दूसरे प्रतिवादी ने 14 फरवरी, 1959 को एक नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा जारी मांग नोटिस को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की है।

विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने केंद्र सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया और श्री पालखीवाला ने 1 से 3 के बीच हस्तक्षेप किया और दोनों ने याचिकाकर्ता का समर्थन किया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश श्री पुरुषोत्तम त्रिकुमदास ने हमारे सामने निम्नलिखित तर्क उठाए: (1) संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (बी) के तहत। जैसा कि संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 से पहले था, विचाराधीन बिक्री बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि वे भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान हुईं

थी। (2) उक्त बिक्री को बॉम्बे राज्य द्वारा संविधान की धारा 286 (1) के स्पष्टीकरण के तहत बिक्री कर से छूट दी गई थी। क्योंकि वस्तुएं बॉम्बे के अलावा अन्य राज्यों में उपभोग के उद्देश्य से वितरित की गई थीं; (3) बिक्री बॉम्बे राज्य यानी नई दिल्ली के बाहर की गई थी, और इसलिए उन्हें भी संविधान की धारा 286 (1) (क) के तहत छूट दी गई थी और (4) प्रथम प्रत्यर्थी केवल निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारण के पूर्व आदेश में हस्तक्षेप कर सकता था, अर्थात् 31 मार्च, 1955, और यह कि उक्त अवधि बीत जाने के बाद, उसे अधिनियम की धारा 31 के तहत संशोधन में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं थी।

पहला बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। मामले में एक और यदि याचिकाकर्ता उस बिंदु पर सफल होता है, तो विचार के लिए कोई अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

पहला प्रश्न संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किए जाने से पहले संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (बी) की व्याख्या पर आधारित है। उक्त लेख पढ़ा गया;

"(1) किसी राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगाएगा या लागू करने को अधिकृत नहीं करेगा, जहां ऐसी खरीद की जाती है।

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में वस्तुओं के आयात या निर्यात के क्रम में।"

इस अनुच्छेद के तहत, यदि याचिकाकर्ता द्वारा भारत सरकार को बिक्री भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान हुई थी, तो बॉम्बे राज्य के पास उक्त बिक्री पर बिक्री कर लगाने की कोई शक्ति नहीं होगी।

भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान" वाक्यांश क्या बताता है? वाक्यांश के महत्वपूर्ण शब्द "आयात" और "पाठ्यक्रम में" हैं। "आयात" शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति की दृष्टि से "लाना" है। इसलिए भारत के क्षेत्र में वस्तुओं का आयात करने का अर्थ है विदेश से वस्तुओं को भारत के क्षेत्र में लाना। "पाठ्यक्रम" शब्दों का अर्थ है "एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रगति"। इसलिए आयात का क्रम एक बिंदु से शुरू होता है और दूसरे पर समाप्त होता है। यह तब शुरू होता है जब माल विदेश में सीमा शुल्क बाधा को पार करता है और तब समाप्त होता है जब वे आयातक देश में सीमा शुल्क बाधा को पार करते हैं। ये शब्द इस न्यायालय द्वारा त्रावणकोर-कोचीन राज्य बनाम शुनमुघा विलास काजू कारखाना (1) मामले में न्यायिक जांच का विषय थे। इन शब्दों का निर्माण करते हुए, पतंजलि शास्त्री सी. जे. ने पृष्ठ 62 पर कहा:

"शब्द "पाठ्यक्रम" व्युत्पत्ति की दृष्टि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की गति को दर्शाता है, और अभिव्यक्ति "के दौरान" न केवल उस अवधि का तात्पर्य है जिसके दौरान आंदोलन प्रगति पर है, बल्कि एक जुड़े हुए संबंध को भी स्वीकार करता है।"

पाठ्यक्रम की सीमाओं के संबंध में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने पृष्ठ 68 पर टिप्पणी की:

"इसलिए, यह मानना तर्कसंगत प्रतीत होगा कि भारत के क्षेत्र में आयात का मार्ग या निर्यात तब तक शुरू या समाप्त नहीं होता है जब तक कि माल सीमा शुल्क बाधा को पार नहीं कर जाता।"

दास, जे., जैसा कि वे तब थे, अपने असहमत निर्णय में कथित शब्दों की व्याख्या पर पतंजलि शास्त्री, सी. जे. से व्यावहारिक रूप से सहमत थे। विद्वान न्यायाधीश ने पृष्ठ 92 पर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया:

"पाठ्यक्रम" शब्द मेरे दिमाग में क्रमिक और निरंतर प्रवाह, एक प्रगति, एक यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने या प्रगति के विचार को व्यक्त करता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ और तात्पर्य गति, एक आगे की गति है। वाक्यांश "इन द कोर्स ऑफ" में स्पष्ट रूप से उस अवधि का संदर्भ है जिसके दौरान आंदोलन चल रहा है। इसलिए, "भारत के क्षेत्र से बाहर माल के आयात और निर्यात के दौरान" शब्द स्पष्ट रूप से उस अवधि को शामिल करते हैं जिसके दौरान माल अपनी आयात या निर्यात यात्रा पर होता है।"

हम विद्वान न्यायाधीशों की उपरोक्त टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। कहा जा सकता है कि माल के आयात का क्रम तब शुरू होता है जब माल अपनी आयात यात्रा में प्रवेश करता है, यानी जब वे विदेश के सीमा शुल्क अवरोध को पार करते हैं और तब समाप्त होता है जब वे आयातक देश के सीमा शुल्क अवरोध को पार करते हैं।

अगला सवाल यह है कि यह कब कहा जा सकता है कि आयात यात्रा के दौरान बिक्री होती है? इस न्यायालय ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य बनाम द बॉम्बे गो लिमिटेड (2) ने अभिनिर्धारित किया कि एक बिक्री जो निर्यात का कारण बनती है, वह बिक्री है जो माल के निर्यात के दौरान हुई थी। यदि ए, भारत में एक व्यापारी, लंदन में एक व्यापारी को अपना सामान बेचता है और माल को जहाज द्वारा लंदन ले जाकर लेन-देन करता है, तो उक्त बिक्री जो निर्यात का कारण बनती है, संविधान की धारा 286 (1) (बी) के तहत बिक्री कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त है। यही सिद्धांत उन वस्तुओं के विपरीत मामले पर लागू होता है जिनके कारण भारत में वस्तुओं का आयात होता है। इस न्यायालय ने फिर से त्रावणकोर-कोचीन राज्य बनाम सणमुघा विलास काजू कारखाना (1) मामले में इस सिद्धांत को माल के पारगमन के दौरान प्रेषण दस्तावेजों के

हस्तांतरण द्वारा राज्य के भीतर माल की बिक्री या खरीद के मामले में विस्तारित किया। यह निर्णय तीन प्रकार की खरीद से संबंधित था, अर्थात् (i) स्थानीय बाजार में की गई खरीद; (ii) आस-पास के राज्य के पड़ोसी जिलों में की गई खरीद; और (iii) अफ्रीका से आयात। अफ्रीका से आयात में दो समूह शामिल थे-एक समूह में वे सामान शामिल थे जो तब खरीदे गए थे जब वे समुद्र में थे और अफ्रीकी बंदरगाहों से कोच्चि या क्विलोन भेजे गए थे: हम दूसरे समूह से चिंतित नहीं हैं। उक्त मामले में बॉम्बे के कुछ कमीशन एजेंटों ने निर्धारिती की ओर से खरीद की व्यवस्था की, एक बैंक के माध्यम से बॉम्बे में प्रेषण दस्तावेजों की डिलीवरी प्राप्त की, जिसने प्रेषण दस्तावेजों के खिलाफ धन का अग्रिम भुगतान किया और इसे गंतव्य पर निर्धारिती से एकत्र किया। इस न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि आयात के पहले समूह के अंतर्गत आने वाली खरीद के संबंध में, कमीशन एजेंट केवल उत्तरदाताओं के एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं और उक्त खरीद आयात का कारण बनती है और इसलिए छूट के दायरे में आती है। यह ऐसा मामला नहीं था जब भारत में एक आयातक द्वारा किसी तीसरे पक्ष को माल बेचा जाता था जब माल समुद्र में होता था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें कोच्चि में एक पक्ष ने बॉम्बे में अपने एजेंट के माध्यम से समुद्र में सामान खरीदा था और एजेंट ने शिपिंग दस्तावेजों के खिलाफ एक बैंक के माध्यम से कीमत का भुगतान किया था। लेकिन विद्वान न्यायाधीश, पतंजलि शास्त्री, सी. जे. ने बहुमत के विचार को व्यक्त करते हुए, छूट के सभी पहलुओं पर विचार किया और निष्कर्षों को इस प्रकार पृष्ठ 69 पर संक्षेप में प्रस्तुत किया।

"हमारे निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है: (1) निर्यात द्वारा बिक्री और आयात द्वारा खरीद अनुच्छेद 286 (1) (बी) (2) के तहत छूट के दायरे में आती है। (3) राज्य में निर्यातक या आयातक द्वारा प्रेषण दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा बिक्री, जबकि माल

सीमा शुल्क बाधा से परे है, छूट के दायरे में है, यह मानते हुए कि राज्य की कराधान की शक्ति ऐसे लेनदेन तक फैली हुई है।"

दास, जे., जैसा कि वे तब थे, अपने असहमत निर्णय में, तीसरे निष्कर्ष पर पतंजलि शास्त्री, सी. जे. से सहमत थे, जिससे हम अब चिंतित हैं। विद्वान न्यायाधीश ने पृष्ठ 94 पर अपना विचार इस प्रकार रखा:

"इस तरह की बिक्री या खरीद, शिपिंग दस्तावेजों की डिलीवरी द्वारा, जब माल अपनी आयात यात्रा पर समुद्र में होता है, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बड़े वाणिज्यिक शहरों में हर दिन बड़े पैमाने पर किए जाने वाले लेनदेन की अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रजातियां थीं और हैं और वास्तव में विदेशी व्यापार की आवश्यक और संगत घटनाएं हैं। यह मानना कि ये बिक्री या खरीद आयात या निर्यात के दौरान नहीं होती हैं, बल्कि विदेशी व्यापार से अलग विशुद्ध रूप से सामान्य स्थानीय या घरेलू लेनदेन के रूप में मानी जानी चाहिए, स्थिति की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना है। इस तरह के निर्माण से किसी राज्य द्वारा संसद द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क या निर्यात शुल्क के अलावा कर लगाने की अनुमति मिलेगी। समान वस्तुओं पर इस तरह के दोहरे कराधान से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी और निर्यात के मामले में, निर्यातकों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोका जा सकता है और आयात के मामले में, उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ पड़ेगा। यह अंततः हमारे विदेशी व्यापार को बाधित और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और ठीक उसी आपदा को लाएगा जिसे रोकना हमारे संविधान का इरादा और उद्देश्य है।"

विद्वान न्यायाधीश ने अपने निर्णय में उस बड़ी कठिनाई पर भी विस्तार से विचार किया जो एक भारतीय आयातक को होगी यदि उसे भुगतान के बदले शिपिंग दस्तावेजों की डिलीवरी द्वारा समुद्र में माल बेचने की अनुमति नहीं दी गई थी। यद्यपि उस मामले को एक अलग स्थिति से निपटाया गया था, हम विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों से सहमत हैं कि एक आयातक, यदि वह प्रेषण दस्तावेज प्राप्त करता है, तो माल में सहायक संपत्ति जब वे समुद्र में होते हैं तो उसे भुगतान के खिलाफ प्रेषण दस्तावेज वितरित करके तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर सकता है और ऐसी बिक्री आयात के दौरान की जाती है।

आयात-बिक्री के संबंध में कानूनी स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है; (1) माल के आयात का क्रम उस समय शुरू होता है जब माल विदेश के सीमा शुल्क अवरोध को पार करता है और माल के सीमा शुल्क अवरोध को पार करने के बाद आयातक देश में एक बिंदु पर समाप्त होता है; (2) वह बिक्री जो आयात के दौरान होती है वह बिक्री है; (3) जब माल समुद्र में होता है तो आयातक द्वारा माल की खरीद, शिपिंग दस्तावेजों के बदले भुगतान करना भी आयात के दौरान की गई खरीद है और (4) माल के आयातक द्वारा बिक्री, माल में संपत्ति के भुगतान के खिलाफ स्वामित्व के दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद या अन्यथा, इसी तरह की प्रक्रिया से किसी तीसरे पक्ष को दिए जाने के बाद भी की जाती है।

अगला सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा भारत सरकार को की गई बिक्री आयात के दौरान की गई बिक्री है। ऊपर वर्णित तथ्यों से, यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के साथ किए गए पहले के अनुबंधों के अनुसार, परिवहन दस्तावेजों को वितरित किया, जिसमें माल के समुद्र में होने पर भुगतान के लिए सरकार को लदान का बिल भी शामिल था। पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह

माना जाना चाहिए कि बिक्री चौथे सिद्धांत के तहत आती है और इसलिए वे बिक्री थीं जो भारत में माल के आयात के दौरान हुई थीं। लदाई का बिल "एक लेखन है, जिस पर जहाज के मालिक की ओर से हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें माल की प्राप्ति को स्वीकार किया जाता है, और ऐसी शर्तों के अधीन यात्रा के अंत में उन्हें वितरित करने का वचन दिया जाता है जो लदाई के बिल में उल्लिखित हो सकता है। वाणिज्यिक दुनिया में यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि लदान का बिल माल का प्रतिनिधित्व करता है और इसका हस्तांतरण माल के हस्तांतरण के रूप में संचालित होता है, लदान के बिल के हस्तांतरण का कानूनी प्रभाव बोवेन, एल. जे. द्वारा सैंडन ब्रदर्स बनाम मैकल-एन एंड गो में स्पष्ट किया गया है। (1) इस प्रकार पृ. 341 में:

"लदान के नोटों के शोधन के बारे में कानून उतना ही स्पष्ट है जितना कि मेरी राय में सभी यूरोपीय व्यापारियों की प्रथा को अच्छी तरह से समझा जाता है। समुद्र में वाहक के हाथों में एक माल अनिवार्य रूप से भौतिक वितरण में असमर्थ है। पारगमन और यात्रा की इस अवधि के दौरान, कानूनी व्यापारी द्वारा लेडिंग के बिल को सार्वभौमिक रूप से इसके प्रतीक के रूप में मान्यता दी जाती है, और लेडिंग के बिल का इंडोर्समेंट और डिलीवरी कार्गो की प्रतीकात्मक डिलीवरी के रूप में काम करती है। जब भी पक्षकारों का इरादा होता है कि संपत्ति को उसी तरह पारित किया जाना चाहिए जैसे समान परिस्थितियों में संपत्ति को माल की वास्तविक डिलीवरी से गुजरना पड़ता है, तो माल में संपत्ति इस तरह के परिशोधन और लेडिंग बिल की डिलीवरी से गुजरती है और माल में ऐसी संपत्ति को पारित करने और उसके पूर्ण कब्जे के लिए पुष्टि के मालिक के अधिकार को पूरा करने के उद्देश्य से, माल का बिल, जब तक कि माल की पूरी

डिलीवरी किनारे पर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं की जाती है जो इसके तहत सही दावा करता है, एक प्रतीक के रूप में लागू रहता है, और इसके साथ न केवल माल का पूर्ण स्वामित्व होता है, बल्कि मालवाहक और जहाज के मालिक के बीच परिवहन के अनुबंध द्वारा बनाए गए सभी अधिकार भी होते हैं। यह एक चाबी है जो एक सही मालिक के हाथ में है, जिसका उद्देश्य गोदाम के दरवाजे को खोलना है, तैरता हुआ या स्थिर, जिसमें माल होने की संभावना हो सकती है।"

हमने परिच्छेद को विस्तार से उद्धृत किया है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से इस विषय पर कानून बताता है। यह विवादित नहीं है कि भारत में भी कानून इंग्लैंड के समान है। माल के बहते समय माल के बिल की डिलीवरी माल की डिलीवरी के बराबर होती है। विद्वान वकील स्वीकार करता है कि आम तौर पर ऐसा ही होगा, लेकिन तर्क देता है कि वर्तमान मामले में, अनुबंध स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पक्षों का इरादा यह था कि जब तक वास्तविक डिलीवरी नहीं की जाती, तब तक माल में संपत्ति खरीदार को नहीं जाएगी। दोनों अनुबंध समान हैं और वे सरकार द्वारा निर्धारित मानक शर्तों का पालन करते हैं। अनुबंधों की मुख्य शर्तों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

पहला खंड "विक्रेता" शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है चीनी बेचने वाला पक्ष और "सरकार" शब्द का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति। खंड 2 में निर्धारित किया गया है कि सरकार द्वारा अनुमोदित उपयुक्त बोरे का उपयोग चीनी के आयात के लिए किया जाना चाहिए। खंड 3 में परिवहन के समय सरकार द्वारा चीनी की गुणवत्ता, वजन और पैकिंग का निरीक्षण करने का प्रावधान है। खंड 4 में कहा गया है कि चीनी को

विशेष बंदरगाहों पर भेजा जाएगा। खंड 5 विक्रेताओं को चार्टर शर्तों पर स्टीमर लगाने के लिए मजबूर करता है, सरकार को जहाज की रेल से निर्वहन के बंदरगाह पर माल की डिलीवरी लेने का अधिकार देता है और विक्रेताओं पर स्टीव-डोरिंग, जहां आवश्यक हो वहां लाइटर, क्रेन किराए पर लेने, डॉक बकाया और पायलट के खर्चों को पूरा करने का बोझ लगाता है। खंड 6 आपूर्ति के लिए भुगतान के तरीके से संबंधित है; उस खंड के तहत विक्रेताओं को खाद्य और कृषि मंत्रालय में सरकार को लागत और माल ढुलाई मूल्य के पूर्ण भुगतान के लिए एक बिल प्रस्तुत करना है; नई दिल्ली, जिसमें तीन परक्राम्य और तीन गैर-परक्राम्य प्रतियों, चीनी के मूल प्रमाण पत्र, गुणवत्ता, वजन और पैकिंग का प्रमाण पत्र, जहाज के मालिकों से एक प्रमाण पत्र है कि माल ढुलाई का पूरा भुगतान किया गया है और यह कि जहाज के मालिकों के पास उस खाते में माल पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं है। खंड 6 (ग) के तहत विक्रेताओं द्वारा अपनी कीमत पर ऋण पत्र खोला जाएगा और भारत सरकार आयात लाइसेंस के उत्पादन पर खरीदी गई चीनी की मात्रा की लागत और माल-भाड़ा मूल्य की सीमा तक आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिए सहमत होगी जो उचित प्राधिकारी को उनके निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने पर जारी की जाएगी। खंड 8 सरकार को अनुबंध की शर्तों के अनुसार चीनी की आपूर्ति करने में विक्रेताओं की विफलता की स्थिति में परिसमापन क्षति के रूप में और/या निर्धारित राशि तक जुर्माने के रूप में किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार प्रदान करता है। खंड 9 सरकार को अनुबंध के किसी भी प्रावधान का पालन करने या निष्पादन करने में विफल रहने की स्थिति में अनुबंध को तुरंत समाप्त करने के लिए अधिकृत करता है। "फोर्स मैजेयूर" शीर्षक के तहत खंड 11 सरकार को प्रदान करता है, यदि प्लेग या अन्य महामारियों के कारण बल प्रयोग, युद्ध, हड़ताल, विद्रोह, विद्रोह, राजनीतिक गड़बड़ी, नागरिक हंगामा, आग या बाढ़ के किसी भी कारण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण या आंशिक रूप से वितरण को रोका या विलंबित

किया जाता है, तो इस तरह से रोके गए या विलंबित मात्रा के लिए अनुबंध को रद्द करने का अधिकार है। विक्रेताओं द्वारा अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, उन्होंने सरकार से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए, ऋण पत्र खोले, विदेशी कंपनियों को आदेश दिए, चार्टर शर्तों पर एक स्टीमर लगाया, विदेशी फर्मों से माल की डिलीवरी ली और जब माल समुद्र में था, तो भुगतान के खिलाफ केंद्र सरकार को स्वामित्व के दस्तावेज वितरित किए और उक्त सरकार ने विक्रेताओं से लाइसेंस लेकर बॉम्बे बंदरगाह पर माल को मंजूरी दे दी।

आइए अब हम अनुबंध की शर्तों की जांच करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे पक्षों के किसी भी इरादे का खुलासा करते हैं कि भुगतान के खिलाफ माल के बिल के वितरण के बावजूद माल में संपत्ति होनी चाहिए। सरकार को न भेजें। जिन परिस्थितियों में पक्षों के बीच अनुबंध किए गए थे, वे इंगित करते हैं कि दोनों पक्ष यह देखने में रुचि रखते थे कि माल में संपत्ति सामान्य तरीके से पारित हो जब शिपिंग दस्तावेज भुगतान के बदले सरकार को सौंप दिए गए थे। विक्रेताओं को उन विदेशी कंपनियों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना पड़ता था जिनके साथ उन्होंने ऋण पत्र खोले थे और सरकार माल का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए उत्सुक रही होगी ताकि विक्रेता माल को अपनी अन्य प्रतिबद्धताओं की ओर या अधिक आकर्षक कीमतों के लिए अन्य खरीदारों की ओर न मोड़ सकें। अनुबंध के तहत पहले के खंडों में सहमत विनिर्देशों के माल को सुरक्षित करने के लिए हर सुरक्षा प्रदान की गई थी और इसलिए माल में संपत्ति को खरीदार को तब तक स्थगित करने का कोई कारण नहीं था जब तक कि माल वास्तव में बंदरगाह में वितरित नहीं किया जाता था। उनकी तरफ के विक्रेता चिंतित होते कि जब माल समुद्र में होता तो संपत्ति गुजर जानी चाहिए, अन्यथा वे बिक्री कर का भुगतान करने के लिए मजबूर होते। न ही प्रत्यर्थियों द्वारा अनुबंधों के खंडों पर भरोसा किया जाता है जो व्यापारिक उपयोग के अनुसार गुजरने वाले माल में

संपत्ति के साथ असंगत हैं। हमारे विचार में, माल की डिलीवरी के समय, जहां आवश्यक हो, दुलाई, क्रेन किराए पर लेना, डॉक बकाया और संचालन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए विक्रेताओं द्वारा की गई देयता, जिस पर विपरीत इरादे को इंगित करने के लिए निर्भरता रखी गई है, का उठाए गए प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि माल में संपत्ति खरीदारों को दिए जाने के बाद भी वह देयता विक्रेताओं पर निर्भर हो सकती है; न ही खंड 9 से 11 जिस पर विद्वान वकील द्वारा मजबूत निर्भरता रखी जाती है, खरीदार को दिए गए माल में संपत्ति के साथ असंगत हैं; उन्हें वैध रूप से उस समय तक लागू किया जा सकता है जब माल में संपत्ति खरीदार को नहीं दी गई हो। यदि विक्रेता खरीदार को दिए गए माल में संपत्ति से पहले अनुबंध के किसी भी प्रावधान के प्रदर्शन का पालन करने में विफल रहता है, तो अनुबंध के खंड 9 के तहत खरीदार अनुबंध को रद्द कर सकता है। तो भी, खण्ड 11 के तहत, यदि दबाव आकस्मिकता द्वारा उच्च समुद्रों पर कोई कल्पित दुर्घटना होती है, तो विक्रेता उस प्रभाव के लिए एक केबलग्राम भेजेगा और खरीदार को पूरे अनुबंध या उसके एक हिस्से को रद्द करने का अधिकार है। यह उस समय पर भी लागू होता है जब माल में संपत्ति खरीदार के पास चली जाती है। यदि, दूसरी ओर, विक्रेता भुगतान के विरुद्ध प्रेषण दस्तावेजों को वितरित करता है और उसके बाद यदि वह बंदरगाह पर माल वितरित नहीं करता है, तो खरीदार के पास नुकसान आदि की वसूली के लिए अन्य उपाय हो सकते हैं। लेकिन वह अधिकार किसी भी अनुबंध का सी. एल. (9) या खंड (11) द्वारा कवर नहीं किया गया है। अनुबंध की सभी शर्तों की जांच इस इरादे का संकेत नहीं देती है कि भुगतान के खिलाफ प्रेषण दस्तावेजों की डिलीवरी के बावजूद माल में संपत्ति खरीदार को नहीं दी जाएगी।

अनुबंध की शर्तों के अलावा, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों पर भी निर्भरता रखी जाती है: (i) विक्रेता ने स्वयं जहाज को किराए पर

लिया; और (ii) सरकार द्वारा जारी लाइसेंस को गैर-हस्तांतरणीय बना दिया गया था। हम यह नहीं देखते कि ये दोनों तथ्य विपरीत इरादे का संकेत कैसे देते हैं। यदि विक्रेता स्वयं एक स्टीमर किराए पर लेता है, जब उसके द्वारा खरीदा गया माल जहाज में लादा जाता है, तो माल में निहित संपत्ति उसके पास चली गई और इसलिए वह उसे सरकार को बेचने की स्थिति में था। यह तथ्य कि लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं था, सरकार को दिए जाने वाले माल की संपत्ति से कोई संबंध नहीं रखता है।

सरकार द्वारा जारी लाइसेंस संबंधित अधिनियम के तहत वैधानिक शक्ति का एक प्रयोग है। चाहे याचिकाकर्ता ने सरकार को माल बेचा हो या किसी तीसरे पक्ष को, उसे लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था। वास्तव में वर्तमान मामले में, विक्रेता को सरकार के साथ अनुबंधों को पूरा करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ लाइसेंस दिया गया था और अनुबंधों को निष्पादित करने के कई दिनों बाद जारी किया गया था, और वास्तव में सरकार ने विक्रेता से लाइसेंस लिया और उनके अधिकारी के माध्यम से माल को मंजूरी दी।

सभी पूर्वगामी कारणों से हम मानते हैं कि माल में संपत्ति भारत सरकार को तब दी गई जब शिपिंग दस्तावेज भुगतान के बदले उन्हें वितरित किए गए थे। यह इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता द्वारा भारत सरकार को माल की बिक्री तब हुई जब माल समुद्र में था। ऐसा होने पर, यह माना जाना चाहिए कि बिक्री भारत में आयात के दौरान हुई थी और इसलिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (बी) के तहत बिक्री कर से छूट दी जाएगी। इस दृष्टिकोण से, विचार के लिए कोई अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। परिणामस्वरूप बिक्री कर के सहायक कलेक्टर के आदेश को अलग कर दिया जाता है और बिक्री कर अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। प्रतिवादी याचिकाकर्ता की लागत का भुगतान करेंगे।

याचिका की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।